

प्रेषक,

डी०ए०सी० महानिरीक्षक,
राज्य
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून: दिनांक: 21 फरवरी, 2008

विषय:— केन्द्रपुरोनिर्धारित योजना "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के अन्तर्गत
898 एकड़/सामुदायिक नई लघु सिंचाई योजनाओं हेतु घनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 1159/ल०सि०/ ए०आई०बी०पी०/ भा०नि०/2007-08 दिनांक 27.12.2007 एवं शासन के पत्र सं० 1340/11-2007-04 (24)/2006 दिनांक 13.11.2007 के क्रम में गुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सलम बी०एम० 15 के कालम-05 पर अंकित लेखाशीर्षकों के लिए सलमक में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा रु० 8443.00 लाख (रुपये बीसवीं करोड़ तीसरी लाख मात्र) की धनराशि आयोजनागत गद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए स्वीकृत 898 नवी योजनाओं हेतु व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1144/11-2007-04(24)/2008 दिनांक 04.10.2007 में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी ध्वितगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 4- उक्त व्यय में बजट, मैन्युअल, वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैंडर/कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा भित्तव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- 6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

- 7- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग निर्धारित समयान्तर्गत तक कर लिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 9- ए0आइ0बी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 10- विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की दशों पर आमरण गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की सरतुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 11- प्रत्येक योजना पर शिलापट्ट/साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिस पर योजना का नाम, योजना की लागत सहित सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित हो।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आव-व्ययक की अनुदान संख्या-20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना (90 प्रतिशत के0स0), 0104-त्वरित सिंचाई लाभ योजना, 24- बृहद् निर्माण कार्य के नामे उाला जायेगा तथा सलग पुनर्विनियोग के कालम-01 की बचतों से ढकन किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-381(P)/वि0 अनु0-4/2008 दिनांक 20 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

गवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या: - 225/11-2008-04(24)/2008/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2 महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 3 वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
- 4 श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6 निजी सचिव, गा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
- 7 अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, राधिका परिसर, देहरादून।
- 10 बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय राधिका परिसर, देहरादून।
- 11 गार्ड फाईल हेतु।

(एस0एस0टी0लिया)
अनु सचिव।

आय-व्ययक प्रपत्र-15

प्रशासनिक विभाग:- लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
(आयोजनागत)

नियंत्रक अधिकारी-मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड
अनुदान संख्या-20 वित्तीय वर्ष 2007-08

(धनराशि लाख रु० में)

बजट प्राविधान एवं लेखापरीक्षा का विवरण	मानक मदवार अथवा वित्तीय वर्ष 12/07 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशिष्ट सार्वजनिक धनराशि	लेखापरीक्षा दिनांक वित्त वर्ष समाप्त होने की तारीख	पुनर्विनिवेश के बाद 8333-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनिवेश के बाद 8333-1 की कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
✓ 4700- मुख्य सिंचाई पर पूर्वीय परिसर							
✓ 09-सिंचाई विभाग की नती योजनाएं				4700-मुख्य सिंचाई पर पूर्वीय परिसर			विशेष 18.10.2007 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सिंचाई विभाग हेतु 8333-5 की कुल धनराशि 100.00 करोड़ की धनराशि लघु सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जाए।
✓ 800- अन्य व्यय				800-अन्य व्यय			उक्त निर्णय के अनुसार में लघु सिंचाई विभाग को वित्तगत 84.43 करोड़ की आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु सिंचाई विभाग के 8333-5 की कुल धनराशि 100.00 करोड़ की धनराशि लघु सिंचाई विभाग के 8333-5 की कुल धनराशि 100.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।
✓ 01-कैपेटीव अथवा अन्य व्यय				01-कैपेटीव अथवा अन्य व्यय			
✓ 05-सिंचाई विभाग की योजनाएं				05-सिंचाई विभाग की योजनाएं			
✓ 24-मुख्य निर्माण कार्य 22000.00	1200.00	10144.44	10000.00	24-मुख्य निर्माण कार्य- 8443.00	10043.00		
योग	1200.00	10744.44	10000.00	8443.00	10043.00		

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनिवेश से बजट अनुमान परिच्छेद 150.131.165 एवं 158 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।


(एसओएस0 टोलियां)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन

शिला अनुभाग-६

संख्या-30142/2003-70-4/2007-08

देहरादून दिनांक २० जनवरी २००८
क/१२

पुनर्विनियोग स्वीकृता

(अर्जुन सिंह)

(आपर सचिव (दिल्ल)

20

(एस०एस० टोलिया)

अनु सदित ।

सेना में,

महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- वित्त अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
२- समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।